Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 24 , 14 अक्टुबर, शनिवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

उत्तर रेलवे चला रहा 78 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा का त्यौहार अपने को साथ मनाने के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने 78 जोड़ी और रेलवे के अन्य जोनों की 42 जोड़ी ट्रेनें इस त्यौहारी सीजन में दो हजार फेरे लगायेगी। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने पूजा के दौरान यात्रियों की ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान सबसे ज्यादा दिल्लीवासी अन्य शहरों की ओर जाते है। ऐसी में उत्तर रेलवे ने 78 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रही है, जबकि अन्य जोन की 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें दिल्ली से होकर आवाजाही करेंगी। यह सभी ट्रेनें इस दौरान दो हजार फेरे लगायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे भीड़ भाड ज्यादा होने पर यात्रियों की सुविधा के लिए आखिरी समय में भी ट्रेनें चलायी जा सकती है। इसकी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे पूरी तरह से तैयार है।

एक क्लिक से निगम कर्मियों के खातों में पहुंच जाएगा वेतन

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर्मियों के खातों में ऑनलाइन माध्यम से साथ के साथ वेतन का भुगतान करने के संबंध में अनुबंध किया है। इस प्रक्रिया में निगम के लेखा विभाग के अतिरिक्त टेक महिन्द्रा भी सहयोग करेगा। इस मॉड्यूल के माध्यम से निगम द्वारा अपने लगभग 57000 कर्मचारियों को 221 करोड़ रपए वेतन का भुगतान एक साथ एक क्लिक में उनके खातों में कर दिया जाएगा। इस संबंध में यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा, जिससे श्रम, मानव संसाधन और समय की बचत होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वेतन भुगतान के साथ-साथ निगम कर्मियों को अन्य सुविधाएं भी दे रहा है। इसमें निगम कर्मचारियों का जितना वेतन होगा, वे तीन महीने तक 90 प्रतिशत ओवर ड्राफ्ट लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ उस समय होगा जब निगम के कर्मियों को किसी कारणवश वेतन मिलने में देरी होगी।

नीरज बवानिया गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने कुख्यात नीरज बवानिया गैंग के 25 हजार रपए का इनामी शातिर बदमाश को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान वरवाला निवासी हरवंश उर्फ लड्डी (30) के रूप में हुई है। करोल बाग थाना इलाके में दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए आगे की छानबीन कर रही है। पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के मुताबिक 27 जुलाई को चांदनी चौक इलाके में आभूषणों की दुकान चलाने वाले वरुण खंडेलवाल के करोल बाग स्थित घर पर 5-6 हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी में घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। बाद में उन आरोपियों के बयान के आधार पर घटना के मास्टरमाइंड हरवंश की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत करने के बाद भी जब आरोपी नहीं पकड़ा गया, तो पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इस बीच 6 अक्टूबर को अपराध शाखा की टीम को सूचना मिली कि आरोपी हरवंश द्वारका इलाके के पोचनपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग स्थल के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर एसीपी जसबीर सिंह की निगरानी और इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के कार्रवाई शुरू की गई और सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।

संदिग्ध हालात में युवक की मौत

नई दिल्ली। शालीमारबाग क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने कंपनी वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त विजय विहार निवासी सुंदरपाल (38) के तौर पर हुई । सुंदरपाल अशोक विहार स्थित एक कंपनी में पिछले आठ वर्ष से काम कर रहा था। बुधवार की उसकी छुट्टी थी, लेकिन सुबह उसे कंपनी से फोन आया कि काम पर आ जाओ। अगर नहीं आए तो कल से काम पर मत आना। इसके बाद पीड़ित काम पर चला गया।

वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर 96 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार के एनएसयूआई के नेतृत्व वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ ने डेमोक्रेसी डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माकपा नेता सीताराम येचुरी, जेडीयू से निष्कासित राज्यसभा सांसद शरद यादव और अनवर अली भी मौजूद रहे। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन पिछले तीन साल में सरकारी नीतियों की वजह से 96 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि पढ़ा-लिखा नौजवान न उभरे।

अगर उनमें चेतना बढ़ेगी तो वे सरकार से सवाल पूछेंगे इसलिए विश्वविद्यालयों पर हमले जारी हैं। सीताराम येचुरी ने वामपंथी दलों और कांग्रेस की विचारधारा के अंतर के बारे में बताया कि कांग्रेस ने जहां धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक आजादी पर ध्यान दिया है वहीं वामपंथी दलों ने इसके साथ आर्थिक आजादी के लिए भी प्रयास किए हैं। शरद यादव ने डीयू के छात्रों को संबोधित कर कहा कि इस बार दिवाली पर दिवाली जैसा माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से व्यापारी से लेकर छात्र, कर्मचारी और आम आदमी परेशान है।

उन्होंने कहा कि देश के हालात पहली बार इतने खराब नहीं हैं, लोकशाही और लोकतंत्र हर वक्त सचेत रहने के लिए आगाह करते हैं। शरद यादव ने एनएसयूआई के डूसू छात्रसंघ चुनाव जीतने वाले पदाधिकारियों से कहा कि इस बार छात्रों ने उन्हें मौका दिया है। डीयू में उनकी जीत पूरे भारत के लोगों की बेचैनी का कारण है।

शरद यादव ने छात्रों से कहा कि तमाम आंदोलन नौजवानों के दम पर ही खड़े किए जाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय पर पूरे देश की नजर रहती है और छात्र नेताओं को खुद को साबित कर देश के सामने एक बेहरीन संदेश देना है। राज्यसभा सांदस अली अनवर ने कहा कि विश्वविद्यालय के नौजवानों के चुनाव जीतने से ही कुछ नहीं होने वाला। उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर कई मुद्दों पर जनता से बात करनी होगी। इस कार्यक्रम में डीयू के कई प्रोफेसर और डूसू के उपाध्यक्ष कुनाल सेहरावत समेत कई छात्र नेता मौजूद रहे।

चीन सीमा पर महत्वपूर्ण दर्रों को जोड़ेगी भारतीय सेना

नई दिल्ली। सिक्किम सेक्टर में डोका-ला गतिरोध के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने चीन से लगती सीमा पर सड़क बनाने के काम में तेजी लाने तथा लिपुलेख, नीती, थांगला और त्सांगचोकला जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रों को अगले तीन साल में जोड़ने का निर्णय लिया है।

एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई की स्थिति पैदा होने की आशंकाओं के मद्देनजर सेना प्रमुख ने सभी कमानों से हर समय पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा है।

सेना के महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह ने शीर्ष सैन्य कमांडरों के पिछले पांच दिनों से यहां चल रहे सम्मेलन के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सेना ने उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर आवागमन सुगम बनाने के लिए सड़क बनाने के काम पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।

चीन की नई चालः डोकाला में धीरे-धीरे बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या

उन्होंने कहा कि सेना की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ सेना फोरमेशनों में संगठनात्मक बदलाव की बारीकियों पर भी गहन मंथन किया गया। उत्तरी कमान के क्षेत्र में सड़क बनाने तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सीमा सड़क संगठन को अतिरिक्त धन राशि देने का भी फैसला लिया गया है।

संप्रुभता के तहत डोका ला पर गश्त कर रहेः चीन

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हथियारों, गोला बारूद और उपकरणों की कमी को दूर करने को प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है। जनरल रावत ने कहा कि खरीद के समय संतुलित रुख अपनाया जाना चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेना को किस चीज की सबसे अधिक जरूरत है।

बयानः विदेश मंत्रालय ने कहा- डोकलाम में कोई नया घटनाक्रम नहीं

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन में सेना की मारक क्षमता और दक्षता का चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर जोर दिया था। देश को बाहरी तथा भीतरी खतरों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने सेना से कहा कि वह दुश्मन ताकतों से निपटने के लिए ताकत बढ़ाए।

गुजरात में भाजपा की डूबती नाव को चुनाव आयोग के तिनके का सहाराःकांग्रेस

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं करने के चुनाव आयोग के कदम को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर बरसते हुए आरोप लगाया कि वह निवार्चन आयोग के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में भाजपा की डूबती नाव को चुनाव आयोग के तिनके का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात के चुनाव एक साथ नहीं करवाने के फैसले के विरोध में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर उसके समक्ष विरोध जताने, अदालत में इस फैसले को चुनौती देने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददातओं से कहा, 'भाजपा समय की सही कसौटी पर खरी उतरी परंपरा (दोनों राज्यों के चुनाव साथ में कराने) को तोड़ने की सबसे बड़ी दोषी है। इस बदलाव के लिए हताश एवं बौरायी हुई भाजपा द्वारा अंतिम समय में यह प्रयास इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 अक्तूबर को गुजरात में सांता क्लाज की तरह विभिन्न घोषणाएं कर सकें।

उन्होंने कहा कि 2002-03 को यदि छोड़ दें तो 1998 से दोनों राज्यों में एक साथ ही चुनाव करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि 2002-03 में गुजरात दंगों के कारण साथ में चुनाव नहीं हुए।' सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के अप्रैल 2001 के एक कायार्लय परिपत्र का उल्लेख किया है। इसके अनुसार चुनाव आयोग को राज्य में 46 दिनों के भीतर चुनाव करवाना चाहिए। किन्तु इस नियम को पूर्व में कई बार तोड़ा गया।

रेलवे का फ्रंट लाइन स्टाफ ड्यूटी पर इस्तेमाल नहीं करेगा वाट्सअप

ड्यूटी के दौरान वाट्सअप चलाया तो खैर नहीं

नई दिल्ली। पिछले महीने उत्कल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल के फ्रंट लाइन स्टाफ को आदेश दिया कि वह ड्यूटी के दौरान वाट्सअप का इस्तेमाल किया तो खैर नहीं। ड्यूटी के दौरान वाट्सअप चलाने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर डीओएम/जी ने 25 सितम्बर 2017 को पत्र जारी कर सभी फ्रंट लाइन कर्मियों को निर्देश दिया कि वह ड्यूटी के दौरान वाट्सअप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पिछले महीने दुर्घटनाग्रस्त हुए उत्कल एक्सप्रेस को लेकर उत्तर रेलवे खास कर दिल्ली मंडल का बड़ी फजीहत हुई थी। सूत्र बताते हैं कि अफसरों तक यह सूचना पहुंची थी कि फ्रंट लाइन कर्मी ड्यूटी के दौरान वाट्सअप चलाते रहते हैं। जिसकी वजह से उनका ध्यान ड्यूटी पर कम रहता है।

इससे देखते हुए सीनियर डीओएम/जी ने दिल्ली डिविजन के सभी फ्रंड लाइन कर्मचारियों जिनमें दिल्ली मंडल के सभी स्टेशन डायरेक्टर, पाइंटमैन, गार्ड आदि को निर्देश दिया है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने माना कि इस तरह के आदेश फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद अगर कोई ड्यूटी के दौरान वाट्सअप चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रोहिंग्या मुस्लिम को वापस भेजने पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों के मामले में सुनवाई के दौरान सभी पार्टियों को चर्चा के लिए समय दिया है और इस मामले की सुनवाई को 21 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने पर लगाई रोक लगा दी है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि दलीलें भावनात्मक पहलुओं पर नहीं बल्कि कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी कि वे किसी भी आकस्मिक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। पीठ ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के उस रूख का विरोध किया था कि जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या मामले की याचिका न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या संकट पर कहा था कि मानवीय पहलू और मानवता के प्रति चिंता के साथ-साथ परस्पर सम्मान होना भी जरूरी है।

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हलफनामे में रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की बात करते हुए उन्हें किसी कीमत में भारत में रहने की इजाजत नहीं देने की बात कही गई। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में रहने की इजाजत नहीं दी सकती है। हलफनामे के मुताबिक भारत में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 40 हजार से अधिक हो गई है। हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि ऐसे रोहिंग्या शरणार्थी जिनके पास संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भारत से जाना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने की योजना पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था।

श्रीनगर में चोटी कटने पर हंगामा, रेल सेवा बाधित

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में चोटी कटने की घटना को लेकर अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर घाटी में शुक्रवार को रेल सेवा बाधित रही। इस दौरान सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर के कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह से घाटी में सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चली, लेकिन दोपहर बाद से रेलगाड़ियों की आवाजाही निलंबित कर दी गई। उन्होंने कहा कि दोपहर बाद मध्य कश्मीर से बारामुला में श्रीनगर-बडगाम की रेल लाइन पर कोई रेलगाड़ी नहीं चली। इसी तरह जम्मू क्षेत्र में दक्षिण कश्मीर से बनिहाल में श्रीनगर-अनंतनाग-काजीगुंड रेल लाइन पर रेल सेवाएं निलंबित रहीं।

शैक्षणिक संस्थान लगातार दूसरे दिन बंद

श्रीनगर महिलाओं की चोटी कटने की घटनाओं के खिलाफ अलगाववादी नेताओं के प्रदर्शन के आह्वान के बाद घाटी के शिक्षण संस्थान शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बंद रहे। जिसके बाद प्रशासन ने गुरुवार को एहतियातन सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए थे। वहीं कश्मीर के मंडलीय आयुक्त बसीर अहमद खान ने अपने नए आदेश में सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को एहतियातन बंद रखने आदेश दिए हैं।

जेएनयू छात्र संघ का आज सीबीआई मुज़्यालय पर प्रदर्शन

नजीब की मां ने राष्ट्रपति से लगाई हस्तक्षेप की गुहार

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय के छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस ने एक वर्ष से भी अधिक समय से गायब चल रहे बेटे का कोई सुराग न लगने को लेकर इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति के नाम भेजे पत्र में फातिमा नफीस ने मांग की है कि जांच एजेंसी को निर्देश दिये जाएं कि वह सरकारी व राजनीतिक दखल से ऊपर उठकर मामले की जांच करें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। अब इस मामले में जेएनयू छात्र संघ शुक्रवार सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहा है। फातिमा ने कहा है कि पिछले एक साल से नजीब के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक नजीब का पता नहीं लगा है। इस मामले में एक अपील जारी की गई है। अपील में कहा है कि पिछले साल 14 अक्टूबर को जेएनयू के माही-मांडवी हॉस्टल एबीवीपी के लोगों ने एमएससी बायोटेक के छात्र नजीब की बुरी तरह पिटाई की और मारने की धमकियां दीं थी। इसके बाद 15 अक्टूबर 2016 से नजीब गायब है। नजीब की मां जब पुलिस में रिपोर्ट कराने गयीं तब उनको उन एबीवीपी के लड़कों का नाम लिखने से पुलिसवालों ने रोक लिया। उसके बाद जेएनयू छात्रसंघ और वहां मौजूद तमाम गवाहों ने भी अपने बयानों समेत कंप्लेंट पुलिस को दी। 15 तारीख को ही एक कंप्लेंट जेएनयू प्रशासन को दी गयी थी।

ये घटना 14-15 अक्टूबर 2016 की है और आज इस घटना को एक साल होने को आया है। इस बीच भाजपा द्वारा बिठाये गए जेएनयू प्रशासन और पुलिस और सीबीआई ने जांच में लचरपन दिखाया और एबीवपी के लोगों को बचाने में ही दिलचस्पी दिखाई। सीबीआई को केस मिलने के बाद से कोर्ट में 2 डेट हो चुकी हैं, लेकिन सीबीआई की जांच में कुछ भी हल नहीं निकला है। लिहाजा फातिमा ने सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

एक साल से चल रही न्याय की लड़ाई :

जेएनयू प्रशासन ने नजीब के गायब होने के बाद कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभायी।

जब छात्र- छात्राओं ने कंप्लेंट की तब एबीवीपी के लोगो को बचाने की हर संभव कोशिश की गयी। फिर भी प्राक्टर की प्राइमरी रिपोर्ट में एबीवीपी के चार लोगों को दोषी पाया गया। खुद प्रशासन की सिक्योरिटी,वार्डन ने अपनी रिपोर्टों में लिखा कि एबीवीपी के लोगों ने नजीब को पीटा था, लेकिन उस रिपोर्ट को ही बदल दिया। नजीब को लेकर एक भी उनके परिवार से संपर्क नहीं साधा। पहले दिन से ही पुलिस ने अपना सारा ध्यान एबीवीपी के लोगों को बचाने में लगाया, न कि नजीब को ढूंढने में पुलिस ने नजीब को पीटने वाले और धमकी देने वालों का नाम एफआईआर में नहीं आने दिया।

बीच- बीच में जांच को गुमराह करने के लिए कुछ सुनियोजित खबरें भी चलवायीं। कोर्ट की फटकार के बावजूद कुछ भी कंक्रीट नहीं निकाला सीबीआई ने तो और भी असंतोषजनक तरीके से जांच की शुरु आत की और गवाहों के ही बयान लेने में 3 महीने से ज्यादा लगा दिए।

संपादकीय

शर्मसार करती भुखमरी

ये खबर निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है कि पिछले साल की तुलना में वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स- जीएचआई) में भारत तीन पायदान नीचे उतर गया है। वर्ष 2016 में इस सूचकांक में भारत 119 देशों में 97वें स्थान पर था। अब 100वें नंबर पर है। क्या यह तथ्य हमारे लिए गहरी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए कि इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, बांग्लादेश और इराक जैसे देश भी भारत से ऊपर रहे हैं? जीएचआई चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ये हैं- आबादी में कुपोषणग्रस्त लोगों की संख्या, बाल मृत्युदर, अविकसित बच्चों की संख्या और अपनी उम्र की तुलना में छोटे कद और कम वजन वाले बच्चों की तादाद। वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा तैयार भुखमरी सूचकांक में भारत पहले से काफी नीचे आता रहा है। इसकी प्रमुख वजह यहां कुपोषणग्रस्त बच्चों की बड़ी संख्या है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती दो अर्थव्यवस्थाओं में एक है। दुनिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आज इसकी प्रतिष्ठा है। इसके बावजूद भुखमरी सूचकांक में इतना पीछे होना हम सबके लिए गहरे आत्म-मंथन का विषय होना चाहिए। अधिक फिक्र की बात इस मोर्चे पर अपने देश का इस वर्ष और पिछड़ जाना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जन-कल्याण के कार्यक्रमों को प्रभावी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने पर खास ध्यान दिया है। उसने सत्ता में आने के बाद विकास नीति पर नया नजरिया अपनाया। उसका जोर राज्यों को सशक्त करने पर रहा है। सोच यह है कि राज्य सरकारें अपनी खास जरूरतों के मुताबिक कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर स्वरूप देंगी और उन्हें अधिक उत्तरदायित्व के साथ लागू करेंगी। लेकिन इस बीच आखिर कहां चूक हो रही है? समस्या नीतिगत है या खामी अमल में है, इसका अविलंब ठोस आकलन किया जाना चाहिए। आईएफपीआरआई ने एक खास मसले की तरफ ध्यान खींचा है। उसने जिक्र किया है कि भारत की एक फीसदी आबादी के पास देश के कुल धन का आधे से ज्यादा हिस्सा है। इस विषमता का अर्थ यह है कि देश में जो धन पैदा होता है, उसका ज्यादा हिस्सा कुछ हाथों में सिमट जाता है। यानी देश भले लगातार धनी हो रहा हो, लेकिन उसका लाभ सभी तबकों को नहीं मिल रहा है। इस कारण भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि सरकार ने सबको पोषण उपलब्ध कराने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं तथा कई तरह की व्यवस्थागत समस्याओं के कारण इनके लाभ देश के सभी हिस्सों और तबकों तक नहीं पहुंच पाते। ये ऐसे अप्रिय तथ्य हैं, जिन पर सरकारों को तुरंत ध्यान देना होगा। उन्हें समझना होगा कि जीएचआई जैसे पैमानों पर देश की खराब छवि उभरती रही, तो दूसरे क्षेत्रों की तमाम उपलब्धियों पर ग्रहण लगा रहेगा। देश की समूची आबादी को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सर्वोगीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अनिवार्य है।

> दुनिया की एक अहम शक्ति के रूप में आज भारत की प्रतिष्ठा है। इसके बावजूद वैश्विक भुखमरी सूचकांक में निचले पायदान पर होना हमारे लिए गहरे आत्म-मंथन का विषय होना चाहिए।

प्रदूषण का कहर

दिवाली के करीब 8-10 दिन पहले ही दिल्ली-एनसीआर में हवा खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। सोमवार को ही दिल्ली में रियल टाइम एयर इंडेक्स 2.5 पीए (पार्टिकुलेट मैटर) का स्तर जहां औसत तौर पर 307 माइक्रोग्राम/घनमीटर के करीब था, जो सामान्य (60) से पांच गुना था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली-एनसीआर के हालात से हर कोई वाकिफ होगा। इस बार तो दिवाली के पहले ही हालात बेहद खतरनाक और चिंताजनक हो चले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं, जिनमें दिल्ली का स्थान पहला है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अधिकतर मौतें दिल की बीमारी और स्ट्रोक की वजह से होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सालाना 10,000 मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती है। यह आंकड़ा बेहद डरावना है। और जब तक पीएम 2.5 के स्तर को 30 फीसद से नीचे नहीं किया जाएगा तब तक हालात परेशान करने वाले ही बने रहेंगे। यानी शुद्ध और स्वच्छ हवा लगता है दिल्लीवासियों के लिए सपना सा बन गया है। एक और समस्या पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान-हैं जहां पराली जलाने से दिल्ली और उसके आसपास की हवा जहरीली होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की सख्ती के बावजूद किसानों को राज्य सरकारें यह समझाने में विफल रही हैं कि पराली जलाना पर्यावरण और सेहत के लिएकितना नुकसानदेह है। राज्य सरकारें किसानों को नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा वह उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने से बचती है। लेकिन उन्हें इतना तक इल्म नहीं कि सरकार की लापरवाही पर्यावरण और भावी पीढ़ी के भविष्य पर कितना बड़ा चोट है। दो साल पहले एनजीटी ने किसानों को पराली न जलाने के सख्त निर्देश दिए थे। यहां तक तक दिल्ली-एनसीआर के लगे सभी राज्यों से एक प्लान तैयार करने को कहा था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कैसे दिल्ली की आबोहवा साफ रहेगी, सोचने वाली बात है? इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से लेकर उन तमाम संस्थानों को संजीदगी से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अन्य विकल्पों को आजमाने के अलावा सख्त निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटना होगा। ऐसा करके ही दिल्ली को दमघोटू वातावरण से निजात मिल पाएगी।

परिधि/ विशाल तिवारी

तथ्य तो देख लें मंत्री जी

महानगर के अनुसार ही वहां रहने वाले व्यक्ति की संवेदना का स्तर हो जाता है। बिहार के बवसर से सांसद और हाल ही में केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए अश्विनी चौबे का बिहारियों के संदर्भ में बयान कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। मुंबई या दिल्ली का कोई ''ठाकरे'' इस तरीके की कोई बयानबाजी करता तो ध्यान भी देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिहार के यशार्थ को देखने वाला व्यक्ति संवेदनहीन टिप्पणी करता है तो ध्यान देना मजबूरी बन जाता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मुताबिक देश के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बिहार के लोगों की वजह से भीड़ बढ़ जाती है। बिहार के लोग बेवजह छोटी-छोटी बीमारियों को लेकर एम्स पहुंच जाते हैं। जबकि एम्स का ही आधिकारिक 2015-16 का आंकड़े उन्हें गलत साबित करता है। जिसके अनुसार एम्स में 47 फीसद मरीज दिल्ली के होते हैं, यानी करीब आधे। उत्तर प्रदेश 25 फीसद के साथ दूसरे नंबर पर है। बिहार से आने वाले मरीज सिर्फ 15 फीसद हैं। अगर 15 फीसद आते भी हैं तो उनमें से अधिकतर किसी-ना-किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं। बिहार से दिल्ली तक की यात्रा मुफ्त में नहीं होती। किसी भी समय ट्रेन का टिकट पाना ''लोक सभा'' का टिकट पाने से कम नहीं है। दिल्ली में रहने-खाने का खर्च अलग से। एक रिपोर्ट के अनुसार तो अधिकतर मरीज डॉक्टरों द्वारा फिजूल की दवा लिखने से परेशान रहते हैं। सवाल तो अश्विनी चौबे से बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नाते पूछना चाहिए। आखिर बिहार से मरीजों को दिल्ली तक की यात्रा के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? कुछ अंतराल को छोड़ दें तो उनकी पार्टी बिहार में एक दशक से करीब सत्ता में साझीदार है। केंद्र में भी तीन साल से सत्तासीन है। उन्हें बिहार के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। राजग की पिछली सरकार द्वारा पटना में खोले गए एम्स के बावजूद लोग दिल्ली का चक्कर लगाने को क्यों मजबूर हैं? स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए!

तरक्की के रास्ते की व्यवस्था

शेषाद्रि चारी

वैज्ञानिक आविष्कार को लेकर आम युक्ति है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मसला जब आर्थिकी का हो, तो मुझे लगता है कि 'आर्थिक संकट' को सुधारों की जननी कहा जाना चाहिए। आजादी के बाद से 1980 के दशक तक भारत एक ऐसी आर्थिक राह पर आगे बढ़ रहा था, जो सख्त कम्युनिस्ट तो नहीं, लेकिन सोवियत मॉडल जैसा जरूर था। तब तक सरकार 'बंद अर्थव्यवस्था' का पोषण करने वाली नीतियों पर बढ़ रही थी, जो नियंत्रण, नियमन व लाइसेंस-परमिट-कोटा सिस्टम के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली मानी जाती थी। तब सरकार के हस्तक्षेप को आर्थिक विकास के लिए जरूरी और अच्छा माना जाता था। नतीजा यह हुआ कि उस दौर में कोई उल्लेखनीय आर्थिक विकास नहीं हुआ, 'गरीबी हटाओ' के नारे पर 1971 में भारी चुनावी जीत हासिल करने के बावजूद गरीबी कम नहीं हुई, देश आत्मनिर्भर नहीं बना और हम महत्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक न्याय को तरसते रहे।

यह चार दशकों की समाजवादी आर्थिक नीति की विफलता ही थी, जिसने 1991 में एक बड़े संकट को जन्म दिया। तब सरकार को मजबूरन अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा और बेमन से ही सही, राजा चेलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार कमेटी बनानी पड़ी। इस कमेटी ने कई सिफारिशें कीं, जिनमें तर्कसंगत व स्थिर कर ढांचा, कर सुधार, उत्पादकता व स्पर्द्धा में बढ़ोतरी और औद्योगिक विकास व रोजगार को प्रोत्साहन देने की बातें महत्वपूर्ण थीं। कमेटी की सलाह यह भी थी कि देश का टैक्स सिस्टम और करों से जुड़े कानून न सिर्फ बेहतर, बल्कि सरल भी होने चाहिए। इससे लोग स्वेच्छा से सरकार को अपना योगदान देने को प्रोत्साहित होते हैं। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर का विचार संभवत: इसी सोच की उत्पत्ति है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लगातार 'गुड्स ऐंड सिंपल टैक्स' कहते रहे हैं।

'एक देश, एक कर' की परिकल्पना को अंतिम रूप तीन जून को जीएसटी कौंसिल की बैठक में मिला और एक जुलाई, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया। इसे संसार के सबसे बड़े कर सुधार का नाम दिया गया। जीएसटी की बड़ी उपलब्धियों में एक प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक सुधार के लिए दिखाई गई दृढ़ इच्छाशक्ति व राजनीतिक सदिच्छा है। यह भी सच है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के सहयोग और निगरानी से ही जीएसटी कौंसिल वैट और अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग दरों को एक ढांचे में व्यवस्थित करने में शायद सफल नहीं हो पाती।

अपनी शुरुआती मुश्किलों और रुकावटों से अब जीएसटी बाहर निकल चुकी है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न हलकों में इसका प्रभाव दिखने लगा है। लागू होने के अपने पहले ही महीने (जुलाई) में कुल 53 लाख कारोबारियों में से 43 लाख ने अंतिम जीएसटी रिटर्न या जीएसटीआर-1 भरा, जिससे सरकारी खजाने को 95,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं ने भी यह बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया है। यह सही है कि शुरुआत में बाजार की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई, और अविश्वास का ऐसा माहौल भी बना कि इस तरह के व्यापक कर सुधार शायद ही सफल हो पाएं। मगर जल्दी ही विक्रेताओं को टैक्स अंतर का लाभ उपभोक्ताओं को देने से शुद्ध राजस्व में मिलने वाले लाभ के महत्व का एहसास हो गया। इसका नतीजा वस्तुओं की कीमतों में कमी के रूप में सामने आया, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की ढुलाई सुगम हुई और टैक्स भी एक समान हुए। राज्य स्तरीय करों के खत्म होने पर टैक्स संबंधी तमाम बाधाएं, सीमा प्रतिबंध, ढुलाई में देरी और ऐसी ही दूसरी रुकावटें अब दूर हो गई हैं। कंप्यूटरीकृत कर अनुपालन व्यवस्था लागू होने से इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके कारण दलाली और भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगा है।

जीएसटी की वजह से बाजार की ताकतें जैसे-जैसे मजबूत हो रही हैं, सुधार के तमाम दूसरे पहलू भी गति पकड़ने लगे हैं। मेक इन इंडिया पर और अधिक जोर देने और आयात-निर्यात के तंत्र के सरल होने से अब उत्पादक निश्चय ही लाभान्वित होंगे और वे अपने स्टॉक का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। पूरे देश के अब एक बड़ा बाजार बन जाने और बीच में कहीं कोई अवरोध न होने के कारण क्षेत्रीय व्यापार में भी तेजी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जीएसटी ने कई करों को खत्म कर दिया है। ऑटोमोबाइल सेस, इन्फ्रा सेस, मोटर फिडल टैक्स जैसे कर हट जाने से वस्तुओं की तर्कसंगत कीमतें संभव हो सकी हैं। नतीजतन, निम्न व मध्य आय वर्गों में गाड़ियों की खरीद 30 फीसदी तक बढ़ी है। अगर तेल की कीमतों को तर्कसंगत बना दिया जाए और सार्वजनिक परिवहन का तंत्र बेहतर बन जाए है, तो ऑटोमोबाइल व दोपहिया वाहन जैसे क्षेत्रों में निश्चय ही तेजी आएगी और ये रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाएंगे।

एक और क्षेत्र, जहां सुधार की संभावना दिखती है, वह है रियल एस्टेट। रेरा के लागू होने और काम-अनुबंध से जुड़े नियमों में सुधार करने के बाद निर्माण उद्योग में आमूल-चूल बदलाव हो सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में सीमेंट, स्टील, पैंट्स जैसे उत्पादों के कर ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है। स्टांप ड्यूटी भी जीएसटी के दायरे से फिलहाल बाहर है।

बहरहाल, जीएसटी की यह प्रणाली दुनिया भर में अनूठी है और हमारे संघीय ढांचे के अनुकूल तैयार की गई है। हमारे यहां दोहरी जीएसटी प्रणाली है, वस्तुओं और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को सुगम बनाने वाले चालान मिलान तंत्र (प्रति माह तीन अरब चालान का मिलान) बने हैं और इसके सर्वेसर्वा नियंत्रक के रूप में जीएसटी कौंसिल का गठन किया गया है। ये तमाम कवायदें वाकई एक अद्वितीय तंत्र की परिकल्पना को साकार करने वाली हैं।

जीएसटी असल में एक ऐसी मजबूत बुनियाद है, जिस पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार गढ़ना चाहती है। हमारी अर्थव्यवस्था कसौटी और कौशल, दोनों के जरिए निरंतर आंतरिक औद्योगिक विकास करते हुए कुलांचे भरने को तैयार दिख रही है। हमारी एक अद्भुत क्षमता यह भी है कि हम न सिर्फ उत्पादन के एक आदर्श केंद्र हैं, बल्कि उपभोग की भी अपने यहां बड़ी संभावना है। यही वजह है कि हम इस उप-महाद्वीप में सिर्फ एक उभरती हुई आर्थिक ताकत नहीं रह गए हैं, बल्कि एक सौम्य आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

> जीएसटी की वजह से बाजार की ताकतें जैसे-जैसे मजबूत हो रही हैं, सुधार के तमाम दूसरे पहलू भी गति पकड़ने लगे हैं।

विद्युतीकृत परिवहन

सुधरेगी आबोहवा के साथ अर्थव्यवस्था

रमेश कुमार दुबे

हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद सरकार अब देश के परिवहन तंत्र को पेट्रोल-डीजल के बजाय बिजली आधारित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। रेल लाइनों का विद्युतीकरण और 2030 के बाद पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध इसी योजना के अहम पड़ाव हैं। गौरतलब है कि यही साल लंबे सफर के बाद वाहन उद्योग अब आंतरिक दहन वाले इंजन की जगह लीथियम ऑयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रहा है। दुनियाभर की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल वाहनों से तौबा करना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार वाहन तकनीक में हो रहे परिवर्तन के साथ कदमताल कर रही है। यदि भारत इस मुहिम में पिछड़ता है तो न सिर्फ वाहन उद्योग व निर्यात बल्कि 30 अरब डॉलर सालाना राजस्व पैदा करने वाला घरेलू कल-पुर्जा उद्योग भी पिछड़ जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भारत का सालाना आयात 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। इसमें सिमकार्ड, सेटटॉप बॉक्स, एलसीडी, एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम आदि शामिल हैं।

अब से मात्र 13 साल बाद पूरे परिवहन ढांचे को विद्युतीकृत करना आसान काम नहीं है मगर बिजली उत्पादन में जिस रफ्तार से कामयाबी मिल रही है उससे यह लक्ष्य असंभव भी नहीं है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने 2022 तक एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा था, अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। वर्ष 2015 में जहां सौर ऊर्जा में महज 2133 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई वहीं 2017 में इसके 10,000 मेगावाट से ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। अगले चार वर्षों में सौर ऊर्जा में 84,000 मेगावाट बढ़ोतरी का लक्ष्य असंभव नहीं रह गया है। सोलर पैनल में ही रही तकनीकी उन्नति और सौर ऊर्जा की घटती लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ाकर 2,50,000 मेगावाट कर दिया है। हाल ही में सरकार ने टाटा मोटर्स से 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का समझौता किया है। अगले पांच वर्षों के भीतर 50 फीसदी सरकारी वाहन बिजली से चलाने की योजना है। एलईडी बल्ब का उदाहरण सरकार के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। बैटरी-रिक्शा व सोलर-पंप को मिल रही लोकप्रियता भी सरकार का उत्साह बढ़ा रहे हैं। फिर लीथियम ऑयन आधारित बैटरी की कीमतों में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम हो रही है। दूसरी ओर कठोर उत्सर्जन मानकों के कारण पेट्रोल-डीजल वाहनों की कीमत लगातार बढ़ रही है। मौजूदा अनुसंधान को देखें तो अगले पांच वर्षों में डीजल-पेट्रोल व बिजली से चलने वाले वाहनों की लागत लगभग एक समान हो जाएगी। देश को इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन व कल-पुर्जे आयात करने पड़ेंगे। जर्मनी, चीन, अमेरिका जैसे देश पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस कर चुके हैं। इन देशों में वाहन निर्माताओं को 30-40 फीसदी सब्सिडी मिल रही है। 2030 तक पेट्रोल-डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नीति तभी कामयाब होगी जब बैटरी और चार्जिंग संबंधी आधारभूत ढांचा का विकास हो जाए। भारत का संभावित बैटरी बाजार 40 से 55 अरब डॉलर का है, जिसे वह आयात के सहारे पूरा नहीं कर पाएगा। स्पष्ट है देश को बैटरी तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करनी ही होगी। इसी तरह देशभर में वाहन चार्जिंग संबंधी ढांचा बनाना होगा। इस लाल नागपुर में पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया।

एनटीपीसी देशभर में चार्जिंग स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बंगलुरू में बैटरी असेंबलिंग प्लांट है अब कंपनी महाराष्ट्र में एक नया प्लांट लगा रही है जहां हर साल 60,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल निकलेंगे। टाटा मोटर्स अपनी दो सस्ती कारों नैनो और टियागो के इलेक्ट्रिक संस्करण निकाल रही है। टेक्सला कंपनी इलेक्ट्रिक कार लांच करने की तैयारी में है। छह से ज्यादा शहरों और राज्यों में या तो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कर्नाटक सरकार हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई है, जो सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाला पहला राज्य है। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है। ऐसे में परिवहन क्षेत्र में हो रही बिजली क्रांति से न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से 2030 तक सड़क परिवहन में खपत होने वाली ऊर्जा में 64 फीसदी और कार्बन उत्सर्जन में 37 फीसदी की कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहन पेरिस जलवायु समझौते की शर्तों के अनुपालन में भी मददगार बनेंगे। साफ है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह देश में अहम बदलाव लाने वाला साबित होगा।

टीम इंडिया

तेज पिच पर खुली पोल

मनोज चतुर्वेदी

विराट सेना 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से सीरीज हारने के बाद से लगातार विजय पताका फहराए हुए है। वह इस हार के बाद से अब तक जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीजें जीत चुकी है। इन जीतों से यह गुमान होना स्वाभाविक है कि हम विश्व विजेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तब ही गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टी-20 में टीम इंडिया हारी, उससे यह तो लगा कि हमारी कुछ खामियां अभी भी बरकरार हैं और मुश्किल परिस्थितियां होने पर हम पहले जैसे ही कमजोर नजर आने लगते हैं। गुवाहाटी मैच में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने जिस तरह से समर्पण किया, उससे यह जरूर लगता है कि टीम इंडिया जब इस साल दिसम्बर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाएगी तो उसे 2013 के दौरे वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।भारत में वनडे या टी-20 मैच खेले जाने के दौरान आमतौर पर पेस गेंदबाजों के अनुकूल विकेट नहीं मिलते हैं। लेकिन हालात ने गुवाहाटी के विकेट को मुश्किल बना दिया। बारिश की वजह से साफ्ट विकेट में नमी आ जाने से विकेट में असमतल उछाल हो गई। साथ ही गेंद स्विंग होने ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ दूसरा टी-20 मैच खेल रहे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पेस गेंदबाज बेरहेनडॉर्फ ने इन हालात में नियंत्रित स्विंग गेंदबाजी की तो भारतीय उच्चक्रम की समझ में नहीं आ सका कि इस गेंदबाज को कैसे हैंडिल किया जाए। इससे एक बात फिर उजागर हो गई कि मुश्किल हालात में क्लासिकी अटैक का सामना करने में हम अब भी घबरा जाते हैं। इस घबराहट का ही नतीजा था कि दूसरे टी-20 में 27 रन तक स्कोर पहुंचते दोनों ओपनर रोहित शर्मा, शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली और मनीष पांडे पेवेलियन पहुंच चुके थे। यहीं नहीं संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने वाले हार्दिक पांड्या भी इस हालात में टीम के काम नहीं आ सके। अब सवाल यह है कि जब हम घर में इस तरह लीद कर सकते हैं तो दिसम्बर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाकर तीन टेस्ट, छह वनडे और तीन टी-20 की सीरीजें खेलेंगे, तब वहां की मुश्किल स्थितियों में हम क्या करेंगे? हम यदि पिछली सीरीजों का अनुसरण करके हार गए तो हमारे घर में अनुकूल माहौल में एक के बाद एक सीरीज जीतने के कोई मायने नहीं रह जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका को हमेशा ही टफ प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। भारतीय टीम 2013 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी, तो उसे एक मैच बारिश में धुलने की वजह से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था। हालात यह थे कि बारिश ने तीसरे वनडे में खलल नहीं डाला होता तो हम 3-0 से सीरीज हारकर आए होते। इस दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के पेस गेंदबाजों डेल स्टेन, सोतसोबे और मोर्ने मोर्कल का सामना करने में हमारे बल्लेबाजों को लगातार दिक्कत हुई। कभी-कभार एक-दो बल्लेबाज चले भी तो बाकी से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण भारत को बड़ी हारों का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका में हारना कोई नई बात नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका 2015-16 में भारतीय दौरे पर आकर हमें हमारे घर में 3-2 से हरा गई। यह सही है कि भारत के लिए टी-20 सीरीज जीतने का अभी भी मौका है। लेकिन क्लासिक पेस गेंदबाजी के आगे लड़खड़ाने से यह तो संकेत मिलता है कि टीम इंडिया को 2019 में विश्व कप में जौहर बिखेरने हैं तो उसे आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के माहौल में भारत के दिग्गज बल्लेबाजों को शानदार प्रदर्शन करके यह जताना होगा कि वह पेस गेंदबाजी के अनुकूल माहौल में भी जीतना जानता है। हम जब तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे लिए अगले आईसीसी विश्व कप में जीत के दावेदारों में अपना नाम शुमार करा पाना मुश्किल होगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम की परख ऑस्ट्रेलिया करेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उम्मीदों से बहुत खराब प्रदर्शन करके भारत के जीत के गुरूर को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या हम इन सफलताओं को दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोहराने में सक्षम हैं। यह बात इन देशों के दौरों पर ही पता चल पाएगी। गुवाहाटी में जिस तरह से खेते हैं, उससे नहीं लगता है कि हम पेस गेंदबाजी के अनुकूल विकेट पर जीतने का माद्दा रखते हैं। अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो 2019 विश्व कप में हमारा दावा स्वत: ही कमजोर हो जाता है।

फरमान: अब बेटा-बेटी की शादी में नहीं शामिल हो सकेंगे कैदी

लखनऊ। शासन के अड़ंगे से आदर्श कारागार के कैदी बेटी व बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे। छुट्टी के लिए शासनादेश की बाट जोह रहे कैदी असमंजस में हैं। सहालग का मौसम सिर पर है, ऐसे में शासन की हरी झंडी न मिलने पर कैदी मायूस हो गए हैं। ऐसे तकरीबन सौ से ज्यादा कैदी हैं जिन्हें बेटी व बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ़ना था या फिर शादी में शरीक होना था।

छुट्टी मिलने पर वह दिवाली भी परिवार के साथ मनाने का मूड बना चुके थे। अब इन कार्यक्रमों पर शासन का ग्रहण लग गया है। निराश कैदियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होम लीव की मंजूरी के साथ ही पेरोल की मंजूरी देने की गुहार की है। कैदी पुनर्वास योजना के तहत स्थापित की गई देश की इकलौती आदर्श जेल के कैदियों को होम लीव (गृह अवकाश) दिए जाने का प्रावधान है। एडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुति के बाद शासन कैदियों को 15 दिन के होम लीव की मंजूरी देता है। इस दौरान कैदी बच्चों की शादी के साथ घरेलू काम काज के साथ त्योहार आदि में शामिल होते हैं। अमूमन मई-जून के माह में करीब 150 कैदियों को होम लीव की स्वीकृति मिल जाती थी। जून महीने में कमेटी की रिपोर्ट जाने के बाद भी शासन ने कैदियों की होमलीव को मंजूरी नहीं दी। ऐसे में कैदियों का बेटे व बेटी की शादी में शामिल होने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के एक मुल्जिम श्रीहरन उर्फ मुर्गन के रिहाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को रिहाई के पूर्व सजा देने वाली सक्षम अदालत से मंजूरी लेनी होगी।

पेरोल पर भी लगायी रोक

शासन के अड़ंगें की वजह से सूबे की सेंट्रल व जिला जेलों के कैदियों को पेरोल भी नहीं मिल पा रही है जबकि दूसरे प्रदेशों में बराबर कैदियों को पेरोल दिया जा रहा है। पेरोल के तहत कैदी को जेल से बाहर जाने के लिए एक ठोस वजह और कारण बताना होता है।

स्कूल में खराब खाने से बीमार हुई 87 छात्राएं, 20 की हालत गंभीर

मिर्जापुर. यहां के मड़िहान क्षेत्र में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज में खराब खाना खाने से गुरुवार को 87 छात्राएं बीमार हो गई। 20 छात्राओं की हालत गंभीर थी, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया।

छात्राओं को हुई उल्टी-दस्त की शिकायत

दरअसल, गुरुवार की दोपहर लंच में छात्राओं खाना दिया गया। इसके बाद छात्राएं एग्जाम देने बैठ गईं। अचानक एक-एक कर छात्राओं को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। स्कूल प्रशासन ने डॉक्टर को बुलाया और वहीं इलाज करवाया।

20 छात्राओं की हालत गंभीर थी, जिन्हे स्थानीय स्वास्थय केंद्र में एडमिट कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी केपी सिंह और मड़िहान एसडीएम सविता यादव मौके पर पहुंची और छात्राओं का हाल जाना।

राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव हुआ पारित

लखनऊ। नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली आमसभा में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं प्रदेश से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के चुनाव का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हो गया।

इससे पहले, नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक में प्रदेशभर से आए पीसीसी प्रतिनिधियों, जिला एवं शहर अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव अधिकारी किशोर उपाध्याय, सांसद एमए खान एवं पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी तथा अतिरिक्त प्रदेश चुनाव अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जबकि वयोवृद्ध नेता रामकृष्ण द्विवेदी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं प्रदेश से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के चुनाव का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक का संचालन संगठन चुनाव के प्रदेश चुनाव अधिकारी किशोर उपाध्याय एवं प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हनुमान त्रिपाठी ने किया। हम बनेंगे राहुल की ताकत-राजबब्बर राजबब्बर ने कहा कि कांग्रेस में महात्मा गांधी के समय से संगठनात्मक चुनाव की महान परम्परा आज तक कायम है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों का एक फर्ज, धर्म और कर्तव्य बनता है कि जिसने हम सभी को एक नई ऊर्जा और ताकत दी है। गांधी जी के मूल्यों को आगे ले जाने का कार्य किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक स्वर से राहुल गांधी को एआईसीसी का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लेती है।

पटाखों से भरे घर में विस्फोट, मां-बेटी की मौत

अलीगढ़। अलीगढ़ के कस्बा जलाली में गुरुवार देर रात आतिशबाजी में हुए भीषण विस्फोट से दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से मां-बेटी की मौत हो गई। पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य जारी था। विस्फोट से आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हरदुआगंज थाना के कस्बा जलाली के ठा. गोपालदास मंदिर के निकट रफीक पुत्र सुल्तान का दो मंजिला मकान है। वह घर पर ही आतिशबाजी और पटाखे बनाने का कार्य करता है। गुरुवार की रात समय लगभग साढ़े नौ बजे घर में रखे पटाखों में विस्फोट होने के साथ आग लग गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दो मंजिला मकान पूरी तरह से ढह गया। आसपास के मकानों के शीशे टूट गए और दरारें पड़ गईं। विस्फोट के बाद कस्बा के लोग कुछ दरे तक सहमे रहे। बाद में घटनास्थल पर पहुंच गए और मलबे से घायलों को बाहर निकलना शुरू कर दिया और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अफसरी बेगम (45वर्ष) पत्नी रफीक और उसकी बेटी तैयवा को मृत घोषित कर दिया। विस्पोट में शकीला पत्नी मो. हुसैन, मंतशा पुत्री मो. रफीक, आलिया (नौ वर्ष)पुत्री रफीक, अशरफ (14वर्ष) पुत्र रफीक, लालू पुत्र मोहम्मद हुसैन घायल हुए हैं। एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि विस्फोट की सूचना पर एसएसपी राजेश कुमार पांडेय, एसपी देहात डा. यशवीर सिंह, एसडीएम कोल पंकज वर्मा, सीओ अतरौली, समेत कई थानों का पुलिस बल पहुंच गया।

निकाय चुनाव: भाजपा नेता ने कहा- बाहरी नहीं, कार्यकर्ता ही पायेंगे टिकट

गोरखपुर। निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा की एक बैठक में क्षेत्रीय मंत्री डा.धर्मेन्द्र सिंह ने कहा बाहरी नहीं, कार्यकर्ता ही टिकट पायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा से व्यक्ति कुछ पाने के लिए नहीं विचारधारा और राष्ट्र के नाते जुड़ता है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा निर्धारित गाइडलाइन पर कार्यकर्ताओं ने काम किया तो नगर निगम में भाजपा का बोर्ड हर कीमत पर बनेगा।

रायबरेली में भाजपाइयों की धमकी से नाराज महिला डॉक्टरों ने दी इस्तीफे की धमकी

लखनऊ। भाजपा नेताओं के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर गुरुवार को बछरावां सीएचसी की चार महिला डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी है। नाराज चिकित्सकों ने सीएमओ दफ्तर पहुंचकर आपत्ति दर्ज करायी। कहा कि भाजपा के कुछ नेता उन्हें धमका रहे हैं। चिकित्सकों ने गुरुवार को सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि भय की हालत में वे काम नहीं कर पा रही हैं। सीएमओ ने जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीएमओ ने महिला चिकित्सकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। बछरावां सीएचसी में कार्यरत डॉ. सुप्रिया सिंह, डॉ. पारूल सिंह, डॉ. गरिमा चौधरी और डॉ. सुंदारिका यादव ने गुरुवार को इस्तीफे की धमकी दी है। महिला चिकित्सकों ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर कथित भाजपा नेताओं द्वारा काम न करने देने का आरोप लगाया।

महिला चिकित्सकों ने सीएमओ को बताया कि अस्पताल में पहुंचकर खुद को भाजपा नेता बताने वाले तीन लोग ओपीडी नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला चिकित्सकों का आरोप है कि युवक बाजार से दवाएं लिखने का दबाव भी बना रहे हैं। उनके इशारे पर काम नहीं करने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। चिकित्सकों ने कहा कि ऐसी स्थित में वे काम करने को तैयार नहीं है। वे सीएचसी बछरावां में स्वयं को असुरक्षति महसूस कर रही हैं। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे काम नहीं कर पाएंगी।

महिला चिकित्सकों का कहना है कि युवक दबंग किस्म के हैं। वे किसी भी तरह की वारदात उनके साथ कर सकते हैं। डॉ. गरिमा चौधरी और डॉ. पारुल सिंह का कहना है कि सीएचसी में कथित भाजपाइयों द्वारा इतना दबाव और उत्पीड़न किया जा रहा है कि उन्हें काम करते हुए भय लगता है। सीएमओ ने महिला चिकित्सकों की बात को सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें अस्पताल में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे सीएचसी में काम करें, उनकी सुरक्षा की जाएगी। सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं।

बिहार

युवा राजद का राजभवन मार्च, पुलिस के साथ झड़प में कई कार्यकर्ता घायल

पटना। प्रदेश युवा राजद के तत्वावधान में गुरुवार को पटना में राजभवन मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई। झड़प में कई राजद कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजद कार्यकर्ता सृजन घोटाला व भ्रष्टाचार के खिलाफ राजभवन मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल पर ही रोक दिया।

युवा राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं प्रदेश युवा राजद अध्यख मो. कारी सोहैब के नेतृत्व में गर्दनीबाग से राजभवन मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल राजद नेताओं व कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने रोकना चाहा जिसमें वो उलझ गए। इसमें कई राजद कार्यकर्ता व पुलिसकर्मी घायल भी हुए।

मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुलो मंडल ने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाया। श्री मंडल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है।

उन्होंने सृजन घोटाले की अबतक की जांच को सीबीआई से सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर बांध निर्माण में अनियमितता के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की भी मांग की। प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने सृजन घोटाले की तुलना मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले से की। मो. कारी सोहैब ने सृजन मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने राजभवन मार्च के दौरान लाठीचार्ज की।

डीईओ को मिली जान से मारने की धमकी

खगड़िया।

खगड़िया डीइओ सुरेश साहू को अज्ञात बदमाश ने मोबाइल से जान मारने की धमकी दी है।

इस संबंध पीड़ित डीईओ ने चित्रगुप्त थाना में टेलिफ़ोनिक सुचना दी है। घटना गुरुवार की देर शाम की है। पुलिस छानबीन में जुट गयी है। मामले की पुष्टि चित्रगुप्त नगर के थानाध्यक्ष ने भी की है।बताया कि डीइओ के टेलिफ़ोनिक सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गयी है। डीइओ द्वारा दिए मोबाइल नम्बर को खंगाला जा रहा है।सुबह डीइओ से लिखित आवेदन भी लिया जायेगा।इधर डीइओ से सम्पर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल स्वीच ऑफ़ मिला।

दो माह की जांच के बाद सर्जन घोटाले में सीबीआई के हाथ लगे बड़े सबूत

सूत्र के अनुसार काफी हद तक मिली कामयाबी

पटना (ईएमएस)। बिहार की राजनीति में चर्चा में रहा सर्जन मामले में अब करीब दो महीने की जांच के बाद सीबीआई सृजन घोटाले में संबंधित अहम लोगों से पूछताछ को तैयारी कर रही हैं। जिन लोगों से पूछताछ होनी हैं उनमें से अधिकांश भागलपुर में पदस्थापित रहे पूर्व ज़िलाधिकारी हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना हैं कि क़रीब एक महीने से उनकी जांच में,जिसके दौरान पूरा ध्यान साक्ष्यों को जुटाने पर केंद्रित था,उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। इस जांच के दौरान ये भी साफ़ हो गया है कि आख़िर कौन कौन से अधिकारी किस किस स्तर पर या लापरवाही या मिलीभगत से पैसे का ग़बन किया है लेकिन कई जिलाधिकारियों की भी भूमिका भी संदिग्ध रही है।

इस मामले के मुख्य आरोपी सृजन के सचिव प्रिया या उनके पति अमित कुमार या उनके सहयोगी भाजपा नेता विपिन शर्मा को गिरफ़्तारी ना होने पर सीबीआई का कहना हैं कि फ़रार रहकर इन्होंने अपने निर्दोष होने की संभावना को नकार दिया है। उनका दावा है कि जल्द तीनों लोगों की भी गिरफ़्तारी की जाएगी। सृजन घोटाले में क़रीब पचीस लोग फ़िलहाल गिरफ़्तारी के बाद जेल में बंद हैं, कुछ लोगों को रिमांड पर लेकर जांच एजेंसी ने पूछताछ की है लेकिन कई निचले स्तर के अधिकारी भी अभी गिरफ़्त से बाहर हैं। बात दे कि यह पूरा मामला एक हज़ार करोड़ से अधिक का है,अगस्त महीने में इस मामले के उजागर होने के बाद शुरू में ज़िला पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच और गिरफ़्तारी का काम किया था।

इसके बाद में जांच सीबीआई को दे दी गई, इस मामले में कई राजनेताओं के इस घोटाले के मुख्य आरोपी मनोरमा देवी और उनके परिवार से संबंधो के फ़ोटो आए जिनमे केंद्रीय मंत्री,गिरिराज सिंह,शाहनवाज़ हुसैन प्रमुख हैं। सृजन घोटाले में क़रीब पचीस लोग फ़िलहाल गिरफ़्तारी के बाद जेल में बंद हैं, कुछ लोगों को रिमांड पर लेकर जांच एजेंसी ने पूछताछ की है लेकिन कई निचले स्तर के अधिकारी भी अभी गिरफ़्त से बाहर हैं।

बात दे कि यह पूरा मामला एक हज़ार करोड़ से अधिक का है,अगस्त महीने में इस मामले के उजागर होने के बाद शुरू राजद का आरोप है कि जब तक पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच की मॉनिटरिंग नहीं करता असल घोटालेबाज़ नहीं पकड़ में आने वाले है।

विधायकों और सांसदों पर 300 फ़ीसदी लग सकता है जुर्माना

पटना (ईएमएस)। बिहार के लगभग 2 दर्जन विधायकों की संपत्ति में 2010 से 2015 के बीच लगभग 200 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। देश में पहली बार आयकर विभाग विधायकों और सांसदों के संपत्ति की जांच कर रहा है।

बिहार के जिन विधायकों की जांच आयकर विभाग कर रहा है। उसमें जनता दल-यू और भाजपा सहित सभी दलों के विधायक शामिल हैं।

आयकर विभाग ने इन विधायकों से संपत्ति में हुए इजाफे की जानकारी मांगी थी। जिस पर विभाग को कोई संतोषजनक जानकारी विधायकों ने नहीं दी है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि विधायकों द्वारा समुचित जानकारी और दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए जाने पर उन पर 300 फ़ीसदी का जुर्माना लगाने की कार्यवाही हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि आयकर विभाग इन विधायकों पर कार्रवाई करता है, तो इससे विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने सभी सूचनाएं आयकर विभाग को सौंपी हैं। आयकर विभाग की कार्यवाही पर अब इन विधायकों का भविष्य जुड़ गया है। उल्लेखनीय है पिछले वर्षों में 26 लोकसभा के सांसद, 11 राज्यसभा के सांसदों और 257 विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसमें कुछ सांसदों और विधायकों की संपत्ति 500 गुना से ज्यादा बढ़ी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सांसदों और विधायकों पर कार्यवाही करने की मांग की थी।

अकेली महिला से जबरदस्ती की कोशिश, सफल नहीं हुए तो बॉडी में डाल दिया रॉड

पटना.पटना जिले के नौबतपुर में घर से बाहर निकली महिला को गांव के दो युवकों ने पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। महिला ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने उसके शरीर में रॉड डाल दिया और मौके से भाग गए। खून से लथपथ महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

ऑपरेशन टेबल पर तोड़ दिया दम

महिला किसी काम से गांव के बाहर गई थी। उसे अकेला पाकर गांव के धीरज और धर्मेंद्र ने पहले रेप की कोशिश की। जब वे अपनी कोशिश में सफल न हुए तो महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके बॉडी में रॉड डाल दिया।

घटना के बाद महिला को पहले नौबतपुर पीएचसी पर प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया। वहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। पीएमसीएच में प्रसूति रोग विभाग के ऑपरेशन टेबल पर उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक खून बहने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी युवक धीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दूसरे आरोपी धर्मेंद्र की तलाश की जा रही है।

नौबतपुर थाने के इंस्पेक्टर प्रेम राज चौहान शुक्रवार सुबह बलियावन गांव पहुंचे और मृतक महिला के परिजनों से बात की।

पीएम के कारकेड का रिहर्सल, सड़क पर लगा जाम

पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पटना आ रहे हैं। वह पीयू के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को पीएम के कारकेड का रिहर्सल किया गया। कारकेड एयरपोर्ट से निकला और डाकबंगला चौराहा होते हुए साइंस कॉलेज पहुंचा। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। कारकेड में आधा दर्जन ब्लैक कलर की फॉरच्यूनर कार थी। इसके साथ ही ब्लैक कलर की एक रेंज रोवर कार कारकेड के बीच में चल रही थी। पीएम हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह 10.40 बजे आएंगे। यहां से प्रधानमंत्री का काफिला पटेल गोलंबर, राजेंद्र चौक, कर्पूरी गोलंबर, इको पार्क, नवीन सचिवालय, हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, स्वामी नंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, चिल्ड्रन पार्क, करगिल चौक, अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज पहुंचेगा। इस दौरान इन मार्गों पर सुबह 10.15 से गाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा।

सूरत। गुजरात दौरे पर आए युपी के सीएम योगी आदित्य नाथ का सचिन में भव्य स्वागत किया गया। सूरत के चौर्यासी विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के सभी सासंदों विधायकों नगर सेवकों तथा सामाजिक तथा राजनैतिक अग्रणीयों ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का पुष्पहार से भव्य स्वागत किया।

आनंद सबके लिए कार्यक्रम 15 को

सूरत। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, सूरत की ओर से 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम आनंद सबके लिए का आयोजन किया जाएगा।

जिसके तहत 15 अक्टूबर की सुबह 9.30 बजे सिटीलाइट स्थित ओपेरा हाउस के सामने महाराजा अग्रसेन नगर प्राथमिक शाला क्रमांक -160 के 200 बच्चों को हिन्दी मूवी जुड़वा-2 का शो दिखाया जाएगा दिखाने ले जाया जाएगा। इन सभी बच्चों को प्रात: 11 बजे एस.डी. जैन के स्कूल बस द्वारा टीबीजी होटल के निकट सिटी प्लस मल्टिप्लेक्स सिनेमा ले जाया जाएगा। जहां बच्चों को मध्यावकाश के दौरान दोपहर 1.30 बजे अल्पाहार कराया जाएगा।

आज पूरे दिन सूरत तथा भरूच में सीएम

सूरत। सीएम विजय रुपाणी शनिवार को पूरे दिन सूरत तथा भरूच जिले में आयोजित विविध कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे प्रात: 8.45 बजे सूरत एयर पोर्ट पर आएंगे, 9.20 बजे सूरत जिला के पूणीगांव, 9.35 बजे सरभोण, 9.40 बजे कानी, 10.5 बजे महुआ, 10.20 बजे तरसाड़ी, 11 बजे बारडोली, 11.30 बजे खरवासा, दोपहर 12.15 बजे गलतेश्वर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।

चुनाव से पहले सामान्य सभा में पक्ष-विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर किया प्रहार

लगी रही एक दूसरे पर हावी होने की होड़

सूरत। शुक्रवार को विधान सभा चुनाव से पहले की अंतिम सामान्य सभा महानगर पालिका मुख्यालय में आयोजित की गई। सामान्य सभा में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अंत तक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। विपक्ष ने एक तरफ मनपा द्वारा पारित बड़े प्रकल्पों तथा विकास के कार्यों पर को लेकर भाजपा प्रशासकों की मंशा पर सवाल उठाया, वहीं शासक पक्ष के नेताओं ने अपने कार्यों की जमकर सराहना की। विपक्ष ने शासक पक्ष द्वारा किए गए कार्यों को जनता के लिए लालीपाप बताते हुए कहा कि शहर की भोली भाली जनता को लुभाने के लिए भाजपा नए-नए तरीके अपनाती है। पिछले 22 वर्षों में सूरत शहर से होकर बहने वाली विभिन्न खाड़ियों के काम अधूरे होने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वर्षों से शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली खाड़ियों को क्यों नहीं ढका जा सका। मात्र सड़कों के चौड़ीकरण से शहर का विकास नहीं हो जाता। इसके लिए शहर में लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं की तरफ ध्यान देना होगा।

चुनाव सिर पर होने से मनपा शहर की सड़कों की मरम्त का काम कर यह दिखाना चाहती है कि वह जनता की सुविधाओं का कितना ख्याल रखती है। विपक्ष ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर ने अपनी ग्राट का 5 करोड़ सिर्फ वराछा क्षेत्र में खर्च किया।

जबकि मेयर को सम्पूर्ण शहरवासियों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।

ड्राइवर 46.36 लाख का कलर लेकर फरार

सूरत। अंकलेश्वर जीआईडीसी की एशियन पेन्ट कंपनी से ट्रक में 43 लाख 36 हजार का कलर लेकर जयपुर की कंपनी में डिलेवरी करने के लिए लिकला ड्राइवर लाखो का कलर हजम कर फरार होगया होने का मामला चोकबाजार थाने में दर्ज हुआ है । चालक ट्रक जयपुर लेजाने के बजाए चोकबाजार के वेदरोड़ पर ट्रक लेकर अंदर रख्खा पेन्ट गायब कर ट्रक लावारिश अवस्था मे छोड़कर फरार हो गए । चोकबाजार पुलिस के अनुसार कर्नाटक के बैगलोर स्थित पनाथुर रोड निवासी उपेन्द्र लक्ष्मीप्रसाद सोनकर ने 12 अक्टूबर के रोज थाने में मामला दर्ज कर बताया कि हमारी कंपनी के का ट्रक चालक अंकलेश्वर जीआईडीसी की एशियन पेन्ट लिमिटेड कंपनी से 46 लाख 36 हजार की कीमत के कलर के बोक्ष भरकर जयपुर की विश्वकर्मा इंडस्ट्रीयल कंपनी में डिलेवरी करने भेजा था । लेकिन ड्राइवर ने अन्य व्यक्ति ओके साथ मिलकर ट्रक जयपुर के बजाए सूरत के चोकबाजार स्थित वेदरोड़ पर लाकर लाखो रुपये का कलर हजम कर ट्रक लावारिश अवस्था मे छोड़कर फरार हो गया । हादसे के चलते उपेन्द्र भाई की शिकायत पर चोकबाजार पुलिस ने ट्रक चालक सहित अन्य व्यक्ति ओके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

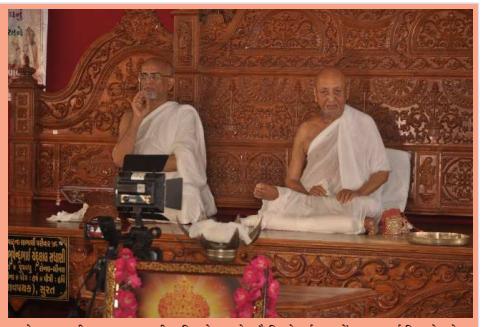

सूरत। राम पावन भूमि पाल रोड़ पर दीक्षा का मुहुर्त निकालते जैन आचार्य। जैन धर्म में दीक्षा का बड़ा ही महत्व है मान्यता के अनुसार दीक्षा का अवसर उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने पूर्व जन्म में उतकृष्ट कर्म किए हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम का मार्ग सर्वोपरि माना गया है। संयम और तप के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। कठिन परीक्षा के बाद ही जैन आचार्यों द्वारा संयम के मार्ग की दीक्षा दी जाती है।

गुमशुदा की तलाश

सूरत। डीसीबी पुलिस कमिश्नर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 6 अक्टूबर 2017 को मकान न.-253, महानंदी सोसायटी, देलड़वागाम, सूरत निवासी मनिषभाई अरबिंदभाई पटेल की 23 वर्षीय पुत्री नीतूबेन लापता है। मध्यम कदकाठी शरीर वाली नीतू का रंग गेहुआं तथा उंचाई 5.2 फीट है। उसने काले रंग का टी-शर्ट तथा भूरे रंग का जींस पैंट पहने हुए है। शहर के कापोद्रा क्षेत्र स्थित के शेरी नं- 5 में रहनेवाली 21 वर्षीय सोनाबेन 5 अक्टूबर से अपने गर से लापता है। शहर के कतारगाम क्षेत्र स्थित मानव धर्म आश्रम के पीछे नीलकमल अपार्टमेंट के म.का.न.-202 में रहने संदीपभाई दिनेशभाई पटेल की 24 वर्षीय पत्नी अल्पना बेन 5 अक्टूबर 2017 से लापता है।

सूरत। पुष्य नक्षत्र के पावन अवसर पर शुक्रवार को शहर में सोने चांदी के आभुषणों की जमकर खरीदारी हुई। शहर के अठवा लाईंस स्थित डी.खुशहाल भाई ज्वैलर्स की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक खरीदारों की लाइन लगी रही। इसके अलावा शहर के प्रसिद्ध ज्वैलरी की दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई।

सूरत। शहर के मगदझा चार रास्ता के निकट वीआर मोल में शुक्रवार को मोक ड्रील का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फायर एण्ड सैफ्टि के कर्मचारियों ने आपातकाल की परिस्थित में किस प्रकार से अपनी सुरक्षा तथा बचाव किया जाए पर मोक ड्रील किया। इस दौरान मोल में आग लगने की सुचना मिलते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ऐसे में किसी प्रकार की भगदड के चलते जान माल की हानी न हो ऐसे व्यवस्था की गई थी। आग की सुचना मिलते ही फायर के अधिकारियो ने घटना स्थल पर पहुंच कर मोर्चा समभाल लिया तथा तकाल लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

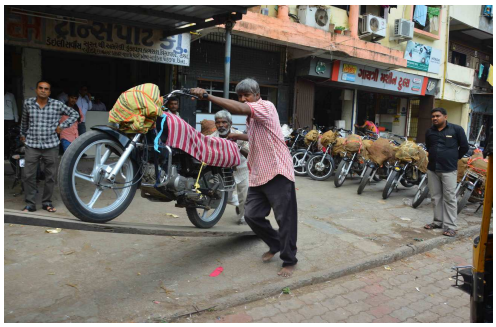

सूरत। हीरा बाजार में दिपावली की झुट्टीया शुरु होते ही रत्न कलाकारों ने गांव की तरफ रुख करना शुरु कर दिया है। दिपावली पर लम्बी छुट्टी होने के चलते रत्न कलाकार घुमने फिरने के लिए अपने साथ अपनी बाईक भी साथ ले जाते है। चित्र में गांव जाने के लिए बाईक को वाहन पर चढाता रत्न कलाकार।

सूरत। आपातकालीन सेवा 108 के कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल कर धरना प्रदर्श कर रहे है। शुक्रवार को 108 कर्मचारियों ने चौक बाजार स्थित जुनी सिविल होस्पिटल में प्रतिक धरना तथा भुख हड़ताल कर अपनी मांगो के समर्थन में प्रदर्शन किया। हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले है ऐसे में 108 कर्मचारी यह आस लगाए बैठे है कि सरकार उनकी मांगो पर ध्यान देगी परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार को आम जनता की नहीं बल्की उद्योग पतियों की चिन्ता है।

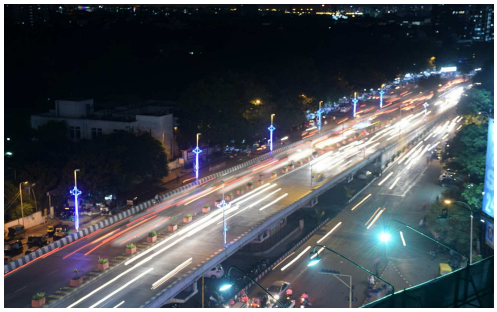

सूरत। दिपावली पर शहर को दुधिया रोशनी से सजनाने के लिए मनपा ने अपनी पुरी ताकत झोक दी है। शुक्रवार को शहर के ज्यादातर फ्लाई ओवर ब्रिजों को रंग बीरंगी रोशनी से जगमगाते हुए देखा गया।

सूरत। संस्कार भारती स्कूल पालनपुर पाटिया में शुक्रवार को ग्रीटिंग कार्ड एण्ड दिया स्लेब्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से मनमोहक ग्रीटिंग कार्ड तथा मिट्टी के दिए बना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

वराछा के एसटी वर्क शॉप में चोरी करने वाले दो जने गिरफ्तार

सूरत। वराछा के लंबेहनुमान रोड स्थित एसटी वर्क शॉप में चोरी करने वाले दो जाने को गेट कीपर ने चोरी के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया । पुलिस सूत्रों के अनुसार वराछा के विधाता एपरमेन्ट निवासी किरीट भाई शशिकांत भाई त्रिवेदी 52 वराछा के लंबेहनुमान रोड स्थित एसटी वर्क शॉप में गेट कीपर है । पिछले डेढ़ माह से एसटी वर्क शॉप के विभागीय यात्रालय में पांच मजदूर काम करने आये थे । इसी दौरान गुरुवार की शाम काम पूण पांचो कामदार कर घर जाने के लिऐ निकले कामदारों की गेट कीपर द्वारा तलाशी लीगई थी इसी दौरान ओलपाड तहसील के मोहम्मद पुर निवासी विशाल रतिलाल राठौड़ तथा राहुल अमृतभाई राठौड़ के पास से 5 किलो एल्युमिनियम का स्क्रैप तथा एक आई पप की दो नग बॉडी सहित 800 रुपये का चोरी का माल जब्त किया । कपनी द्वारा दोनों युवकों पकड़ कर वराछा पुलिस के हवाले किया था । पुलिस ने किरीट भाई की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर दिनों कामदारों को गिरफ्तार किया ।

जोहरी की मोपेड बाइक की डिकी से छह किलो चांदी के आभूषण चोरी

सूरत। वादीफलिया के अंबाजी रोड स्थित रोयल जेम्स नामक दुकान के पास पार्क एक मोपेड बाइक की डिक्की तोड़कर अनजान चोर उच्चके 1 लाख 56 हजार की कीमत के छह किलो चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए होने का मामला सामने आया है । अथवा पुलिस के अनुसार पलसाना तहसील के चल थान गांव स्थित तुलशी पार्क सोसायटी निवासी अंकित विनोदभाई शाह 28 जोहरी है । 11 अक्टूबर के रोज जोहरी अंकित भाई वादीफलिया के अंबाजी रोड पर अन्य जोहरी की दुकान पर चांदी के आभूषण पोलिस करवाने आये थे । इसी दौरान पीड़ित ने अपनी मोपेड बाइक अंबाजी रोड की गॅयल जेम्स के पास पार्क की थी । उसी वक्त अनजान चोर उचक्कों ने बाइक की डिक्की तोड़कर 1 लाख 56 हजार की कीमत के छह किलो चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए ।

वराछा में अधेड़ पर बाइक्स गिरोह ने चाकू से हमलाकर मोबाइल की लूट की

, सूरत। वराछा के हीरा नगर स्थित पटेल नगर के पास से गुजर रहे एक अधेड़ पर बाइक पर सवार होकर आए चार बदमाशों ने चाकू से हमला कर 10 हजार का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हादसे में घायल अधेड़ को उपचार के लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वराछा पुलिस के अनुसार इच्छापोर स्थित सुवली रोड स्थित राजगिरी गांव निवासी संतोष कुमार रंजीत सिंह 40 नौकरी कर परिवार का गुजारा करते हैं. गुरुवार की रात में संतोष कुमार अपनी बाइक पर वराछा के हीरा नगर स्थित पटेल नगर के पास से गुजर रहा था इसी दौरान बाइक और मोपेड बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश चार बदमाशों ने संतोष कुमार को रोककर उस पर चाकू से हमला कर 10 हजार की कीमत के मोबाइल फोन की लूट कर फरार हो गए हादसे में घायल अधेड़ को उपचार के लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया हादसे के चलते पीड़ित के भाई नीरज कुमार की शिकायत पर वराछा पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। हादसे में घायल अधेड़ को उपचार के लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वराछा पुलिस के अनुसार इच्छापोर स्थित सुवली रोड स्थित राजगिरी गांव निवासी संतोष कुमार रंजीत सिंह 40 नौकरी कर परिवार का गुजारा करते हैं.

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेशन के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तामीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com